[2025] 4 एससीआर 1936: 2025 आईएनएससी 596

रेणुका

बनाम

कर्नाटक राज्य और अन्य।

(आपराधिक अपील संख्या 2309/2025)

29 अप्रैल 2025

[पामिडीघंटम श्री नरसिम्हा और जॉयमाल्य बागची, * जे.जे.]

विचारणीय मुद्दा

अपीलकर्ता-पत्नी ने आक्षेपित आदेश को चुनौती दी है जिसके तहत उच्च न्यायालय ने उत्तरदाता -पति के खिलाफ दंड संहिता, 1860 की धारा 498-ए, 324, 355, 504, 506 सह पठित धारा.149 के तहत कार्यवाही को रद्द कर दिया था।

शीर्ष टिप्पणियां

दंड संहिता, 1860 - धारा.498-A, 324, 355, 504, 506सह पठित धारा ..149 - आरोप है कि उत्तरदाता -पति और अन्य ससुराल वालों ने अपीलकर्ता-पत्नी को शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान किया और दहेज की भी मांग की - अपीलकर्ता ने अपने मायके में रहना शुरू कर दिया - 27.10.2020 को, उत्तरदाता -पति और अन्य ससुराल वाले अपीलकर्ता के माता-पिता के घर गए और उसकी आंखों में मिर्च पाउडर फेंका, उसके रिश्तेदारों के साथ चप्पल और पत्थरों से दुर्व्यवहार और मारपीट की - पड़ोसी, एक एस सहित, हस्तक्षेप किया और उन्हें बचाया - प्राथमिकी दर्ज - ससुराल वालों ने उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही को चुनौती दी - उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने केवल सत्तर वर्षीय सास-ससुर के खिलाफ कार्यवाही को रद्द कर दिया - इसके बाद, उत्तरदाता -पति ने एक अन्य समन्वयक एकल पीठ के समक्ष रद्द करने की प्रार्थना की, जिसे अनुमति दी गई - शुद्धता:

अभिनिर्धारित : वर्तमान मामले में, जबकि एक न्यायाधीश ने ससुराल वालों के खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया, अन्य *बातों के साथ-साथ*, घाव प्रमाण पत्र को देखने से पता चलता है कि अपीलकर्ता पर हमला किया गया था और उसे साधारण चोटें आई थीं, एक अन्य न्यायाधीश ने आक्षेपित आदेश द्वारा उत्तरदाता -पति के खिलाफ कार्यवाही को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया

था कि चिकित्सा प्रमाण पत्र शिकायत में आरोपों के अनुरूप नहीं था यानी घाव प्रमाण पत्र यह नहीं दिखाता है कि चोटें एक कुंद हथियार के कारण हुई थीं - आक्षेपित निर्णय का अवलोकन करने के बाद, इस न्यायालय का विचार है कि न्यायाधीश ने प्राथमिकी /आरोपपत्र में आरोपों की विश्वसनीयता या अन्यथा के संबंध में जांच शुरू करके कानून में गलती की है - न्यायाधीश ने प्राथमिकी में वर्णित हमले की प्रकृति की तुलना घाव प्रमाण पत्र से की

---

*रचयिता

और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आरोप असत्य हैं - ऐसा करने में, न्यायाधीश ने कार्यवाही को रद्द करने के लिए एक लघु

विचारण किया था जो कानून में अस्वीकार्य है - यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि उत्तरदाता -पति और अन्य ससुराल वालों द्वारा अपीलकर्ता पर मिर्च पाउडर फेंकने और हमले का आरोप न केवल घाव प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित है जो साधारण चोट का खुलासा करता है, बल्कि पड़ोसी-एस के बयान का भी समर्थन करता है - इस स्थिति को देखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि मामला उन मामलों की श्रेणी में आता है जहां कोई कानूनी सबूत नहीं है या सबूत आरोप पत्र में लगाए गए आरोप के साथ स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से असंगत" है - इस प्रकार, आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया जाता है औरउत्तरदाता -पति के खिलाफ कार्यवाही को पुनर्जीवित किया जाता है। [पैरा 8, 9, 12]

उद्धृत निर्णयजन्य विधि

आरपी कपूर बनाम पंजाब राज्य **[1960] 3 एससीआर 388: 1960 एससीसी ऑनलाइन एससी 21 - पर भरोसा किया गया।**

अधिनियमों की सूची

दंड संहिता, 1860।

प्रमुख शब्दों की सूची

उत्पीड़न; दहेज़ ; हमला ; सत्तर वर्षीय सास-ससुर; घाव प्रमाण पत्र; चिकित्सा प्रमाण पत्र; अंतर्निहित शक्तियां; आपराधिक कार्यवाही को रद्द करना; लघु विचारण; हमले की प्रकृति।

मामले की उत्पत्ति

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 2309/2025

कर्नाटक उच्च न्यायालय सर्किट बेंच धारवाड़ के दिनांक 16.02.2024 के निर्णय और आदेश से

सीआरपी संख्या 101591/2021 में

अधिवक्तागण

*अपीलकर्ता के लिए अधिवक्ता :*सुश्री रुद्राली पाटिल, शांतानु देवांश, सुहास होसमानी, सुश्री रुषिका पाटिल, सबील अहमद, अंशुमन।

उत्तरदाता के लिए अधिवक्ता:

(आनंद संजय एम नुली, वरिष्ठ अधिवक्ता , डीएल चिदानन्द, मैसर्स ऑफ चिदानंदा, मैसर्स नुली और नुली, अभिषेक कन्यालूर, अभिषेक सिंह।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

जॉयमाल्या बागची, न्यायमूर्ति

1. देरी माफ कर दी गई। अनुमति प्रदान की गई।

2. अपीलकर्ता-पत्नी ने आक्षेपित आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 149 के साथ पठित धारा 498-ए, 324, 355, 504, 506 के तहत दिनांक 03.02.2021 की सीसी संख्या 163/2021 में उत्तरदाता -पति के खिलाफ कार्यवाही को रद्द कर दिया इसके बाद 'आईपीसी' के रूप में संदर्भित किया गया है।

    1. उपरोक्त मामला अपीलकर्ता-पत्नी द्वारा दर्ज की गई लिखित शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था: -

        1. अपीलकर्ता और उत्तरदाता के बीच 2012 में शादी संपन्न हुयी ।

        2. दंपति से दो बच्चे पैदा हुए।

3. उत्तरदाता -पति ने भारती हलमनी तमदाद्दी के साथ अवैध संबंध विकसित किए और बाद में घटना से चार महीने पहले अपीलकर्ता को अशिष्ट भाषा में गाली दी। उसने मामले की सूचना तेरादल थाना को दी, लेकिन कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई।

4. उत्तरदाता -पति और अन्य ससुराल वालों ने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और दो लाख दहेज की मांग की।

1.इसके बाद इसे आईपीसी के रूप में संदर्भित

5. दुर्व्यवहार और दहेज की मांग के कारण, अपीलकर्ता तेलसांग में अपने माता-पिता के घर में रहने लगी।

6. 27.10.2020 को, प्रतिवादी-पति और अन्य ससुराल वाले एक कार में उसके मायके आए और उसकी आंखों में मिर्च पाउडर फेंका, उसे और उसके रिश्तेदारों को गंदी भाषा में गाली दी और उन पर चप्पल और पत्थरों से हमला किया। सुवर्णा अंदरि सहित पड़ोसियों ने हस्तक्षेप किया और उन्हें बचाया।

1. अनुसंधान के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से चप्पल और पत्थर बरामद किए हैं। पड़ोसी सुवर्णा आंद्री सहित गवाहों के बयान दर्ज किए गए और उत्तरदाता-पति

और ससुराल वालों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया।

[2025]4 एससीआर

1939

रेणुका बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य

2. ससुराल वालों ने उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही[2] पर विरोध किया। एक एकल न्यायाधीश ने आंशिक रूप से याचिका को स्वीकार कर लिया और सत्तर वर्षीय सास-ससुर के खिलाफ कार्यवाही को रद्द कर दिया, लेकिन अन्य ससुराल वालों के खिलाफ कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी।

3. इसके बाद, उत्तरदाता -पति ने एक अन्य समन्वय एकल पीठ के समक्ष रद्द[3] करने के लिए प्रार्थना की, जिसे अनुमति दी गई।

4. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

5. यह मामला एक परेशान करने वाली तस्वीर को चित्रित करता है। जबकि एक न्यायाधीश ने ससुराल वालों के खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया, अन्य बातों के साथ-साथ, घाव प्रमाण पत्र को देखने से पता चलता है कि अपीलकर्ता पर हमला किया गया था और उसे साधारण चोटें आई थीं, एक अन्य

न्यायाधीश ने आक्षेपित आदेश द्वारा उत्तरदाता पति के खिलाफ कार्यवाही को रद्द कर दिया यह मानते हुए कि चिकित्सीय प्रमाण पत्र शिकायत में लगाये गये आरोप के अनुरूप नहीं था

यानी घाव प्रमाण पत्र से यह नहीं पता चलता है कि चोटें कुंद हथियार के कारण लगी थीं।

6. आक्षेपित निर्णय का अवलोकन करने के बाद, हमारा मानना है कि न्यायाधीश ने प्राथमिकी /आरोपपत्र में आरोपों की विश्वसनीयता या अन्यथा के संबंध में जांच शुरू करके कानून में गलती की। न्यायाधीश ने प्राथमिकी में वर्णित हमले की प्रकृति की तुलना घाव प्रमाण पत्र से की और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आरोप असत्य हैं। ऐसा करते हुए, न्यायाधीश ने कार्यवाही को रद्द करने के लिए एक लघु विचारण किया था जो कानून में अस्वीकार है।

7. आर.पी. कपूर बनाम पंजाब राज्य[4] में इस न्यायालय ने उन मामलों की श्रेणी की गणना की जहां आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग किया जा सकता है। ऐसी ही एक श्रेणी वह है जहां आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों या आरोपों के समर्थन में कोई कानूनी सबूत नहीं दिया जाता है या ऐसे सबूत स्पष्ट रूप से आरोप को साबित करने में विफल रहते हैं। इस श्रेणी

के मामलों को निर्धारित करने के लिए जांच के दायरे के संबंध में और विस्तार से बताते हुए, न्यायालय ने इस प्रकार कहा: -

"6. .....इस वर्ग के मामलों से निपटने में यह महत्वपूर्ण है एक ऐसे मामले के बीच के अंतर को ध्यान में रखने के लिए जहां कोई नहीं है

2.आपराधिक याचिका संख्या 101599/2021

3.आपराधिक याचिका संख्या 101591/2021

4.1960 एससीसी ऑनलाइन एससी 21.

कानूनी साक्ष्य या जहां सबूत हैं जो लगाए गए आरोप के साथ स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से असंगत हैं और ऐसे मामले जहां कानूनी सबूत हैं जो इसकी सराहना पर प्रश्न में आरोप का समर्थन कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। धारा 561-ए के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय इस बात की जांच नहीं करेगा कि विचाराधीन साक्ष्य विश्वसनीय है या नहीं। यह ट्रायल मजिस्ट्रेट का कार्य है, और आमतौर पर किसी भी पक्ष के लिए यह खुला नहीं होगा कि वह उच्च न्यायालय के अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र को लागू करे और यह तर्क दे कि सबूतों की उचित सराहना पर अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोप कायम नहीं रहेंगे..."

(जोर दिया गया)

8. इस दृष्टिकोण का लगातार पालन किया गया है और निर्णयों की एक श्रृंखला[5] में इस न्यायालय ने कार्यवाही को रद्द करने के लिए अपने अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय को बार-बार लघु विचारण शुरू करने

से मना किया है।

9. मामले के तथ्यों के अनुपात को लागू करते हुए, हमें उत्तरदाता -पति और अन्य ससुराल वालों द्वारा अपीलकर्ता पर मिर्च पाउडर फेंकने और हमले के आरोप को मानने में कोई संकोच नहीं है, जो न केवल घाव प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित है जो साधारण चोट का खुलासा करता है, बल्कि पड़ोसी सुवर्णा एंड्री के बयान का भी खुलासा करता है। इस स्थिति को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि यह मामला उन मामलों की श्रेणी में आता है जहां कोई कानूनी सबूत नहीं है या सबूत "आरोप पत्र" में लगाये गये आरोप के साथ स्पष्टतः और स्पष्ट रूप से असंगत है।

---

[5] निहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 315, (पैरा 10.7); ओडिशा राज्य बनाम प्रतिमा मोहंती और अन्य 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 1222, (पैरा 8.2); उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम अखिल शारदा और अन्य 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 820, (पैरा 18); राज्य बनाम एम. मैरिडोस और अन्य 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 47, (पैरा 7); केंद्रीय जांच ब्यूरो बनाम आर्यन सिंह और अन्य 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 379, (पैरा 6); धर्मबीर कुमार सिंह v. झारखंड राज्य और अन्य 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 1894, (पैरा 17); रंजीत मित्तल बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 2926, (पैरा 19)।

10.यह किसी का मामला नहीं है कि घाव प्रमाण पत्र में कोई चोट नहीं देखी गई थी, जिससे हमले का आरोप स्पष्ट रूप से बेतुका या स्वाभाविक रूप से असंभव हो गया था। इस पृष्ठभूमि में, न्यायाधीश के लिए चिकित्सा साक्ष्य के साथ-साथ प्रत्यक्षदर्शी संस्करण को तौलने और कार्यवाही को रद्द करने के लिए एक लघु विचारण शुरू करना अनुचित था। क्या प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य चिकित्सा साक्ष्य के साथ पूरी तरह से असंगत है, यह परीक्षण का विषय है और प्रारंभिक चरण में अभियोजन को समाप्त करने का आधार नहीं हो सकता है।

11.रद्द करने के समर्थन में, न्यायाधीश ने यह भी कहा था कि आरोपों से यह स्पष्ट नहीं है कि हमला किसने किया था और वैवाहिक मुकदमे के लंबित रहने के दौरान अभियोजन अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं था। ये आधार समान रूप से अमान्य हैं।

12.उत्तरदाता -पति और अन्य ससुराल वालों (सास-ससुर को छोड़कर) पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने मिलकर काम किया और अपीलकर्ता और उसके रिश्तेदारों पर हमला किया। जब कई अभियुक्त अपराध करने के लिए समान

इरादा/सामान्य उद्देश्य साझा करते हैं, तो उनमें से प्रत्येक द्वारा हमले में निभाई गई सटीक भूमिका को निर्धारित करना अप्रासंगिक है।

। विद्वान न्यायाधीश आरोपपत्र में निर्विवाद आरोपों की सराहना करने में विफल रहे, रचनात्मक दायित्व को आकर्षित किया और कार्यवाही को इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता कि , यह स्पष्ट नहीं है कि हमला किसने किया था।

13.न्यायाधीश ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने में खुद को भी गलत दिशा दी कि कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण थी और अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग थी क्योंकि कार्यवाही वैवाहिक अदालत के समक्ष लंबित थी। पत्नी पर क्रूरता से जुड़े अपराध हमेशा वैवाहिक विवादों से उत्पन्न होते हैं। तदनुसार, पक्षों के बीच वैवाहिक कार्यवाही के लंबित होने से यह निष्कर्ष नहीं निकल सकता है कि चिकित्सा साक्ष्य और स्वतंत्र गवाह द्वारा समर्थित हमले का आरोप लगाने वाली आपराधिक कार्यवाही की संस्था दुर्भावना और अदालत के दुरुपयोग का परिणाम है।

14.अंत में, यह तर्क दिया जाता है कि वहां वाद और प्रतिवाद हैं और माता-पिता के खिलाफ कार्यवाही को समन्वय पीठ द्वारा रद्द कर दिया गया है। यह देखते हुए कि सास-ससुर सत्तर साल के हैं और प्राथमिकी में कोई कानाफूसी नहीं है कि उन्होंने हमले में भाग लिया था, उनके खिलाफ कार्यवाही को रद्द कर दिया

गया था। प्रथम सूचना प्रतिवेदन/आरोप पत्र में निर्विवाद आरोप स्पष्ट रूप से उत्तरदाता -पति को हमले में शामिल करते हैं। वह एक ही पायदान पर खड़ा है अन्य ससुराल यानी बहनोई/भाभी के साथ जिनके खिलाफ आपराधिक याचिका संख्या 101599/2021 में कार्यवाही रद्द नहीं की गई थी। हालांकि कुछ ससुराल वालों के खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने से इनकार करने वाला आदेश पहले पारित किया गया था, लेकिन यह समझ से परे है कि उत्तरदाता -पति के खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने वाले आक्षेपित आदेश में उक्त आदेश का कोई संदर्भ क्यों नहीं है। उत्तरदाता -पति के खिलाफ कार्यवाही को रद्द करते समय न्यायाधीश का यह दायित्व था कि वह समन्वय पीठ के पहले के निर्णय का उल्लेख करे और एक अलग निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उसके कारणों को अलग करे। ऐसा करने में विफलता न्यायिक औचित्य और अनुशासन

को प्रभावित करती है। न्यायिक परिणामों में निरंतरता एक जिम्मेदार न्यायपालिका की पहचान है। विभिन्न बेंचों से आने वाले असंगत निर्णय जनता के विश्वास को हिलाते हैं और मुकदमेबाजी को एक सट्टेबाज के खेल में कम करते हैं। यह विभिन्न कपटी तीक्ष्ण प्रथाओं को जन्म देता है जैसे फोरम शॉपिंग न्याय की स्पष्ट धारा को खराब करता है। आक्षेपित आदेश न्यायिक सनक और मनमानी के दोष से ग्रस्त है और इस स्कोर पर भी रद्द किए जाने के लिए उत्तरदायी है।

15.उपरोक्त कारणों से, हम दिनांक 16.02.2024 के आदेश को रद्द करते हैं और उत्तरदाता -पति (आर 2) के खिलाफ कार्यवाही को पुनर्जीवित किया जाता है और कानून के अनुसार जारी रहेगा। नतीजतन, अपील की अनुमति दी जाती है।

मामले का परिणाम: अपील की अनुमति दी गयी।

शीर्ष टिप्पणियां - अंकित ज्ञान द्वारा तैयार की गयी ।

यह अनुवाद शिव बचन यादव , पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।